भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6075
जिसका उत्तर मंगलवार 11 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसंधान और विकास

6075. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों को देश में 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत उन्नत कृषि और कटाई और खाद्य प्रसंस्करण मशीनों के निर्माण हेतु अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में 2025 तक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मशीनों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या सरकार देश में इस क्षेत्र में तेजी लाने के लिए राजसहायता/कर प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): भारी उद्योग विभाग में केपिटल गुड्स से संबंधित एक स्कीम है जिसके द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थानों के निकट सहयोग से प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों का विकास करके पूंजीगत वस्तुओं के विभिन्न उप क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाता है।

अब तक कृषि-क्षेत्र (फार्म) या खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी उद्योग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति के अनुसार वर्ष 2014-15 में खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के बाजार का आकार ₹15,600 करोड़ है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, भारी उद्योग विभाग किसी प्रकार की सब्सिडी/कर संबंधी प्रोत्साहन खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी विनिर्माण उद्योग को नहीं दे रहा है।

*****